

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 716 / 2013 / उदयपुर.

मैसर्स टील लिमिटेड, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

### बनाम

- (1) उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर उदयपुर.  
 (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

### एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

### उपस्थित :

श्री गोपीलाल ऐरन, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12 / 02 / 2015

### निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 284 / वेट / 11-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.01.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 23, 55 व 58 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.01.2012 को वेट अधिनियम की धारा 23, 55 व 58 के तहत पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र एवं वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 3,04,500/- एवं देय कर विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 11,560/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.01.2013 से अस्वीकार किये जाने से व्यक्ति होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

१५०१४

लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.16( )टैक्स/सीसीटी/11/241 दिनांक 16.05.2011 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009–10 से सम्बन्धित बिक्री विवरण प्रपत्र व घोषणा-पत्र दिनांक 16.05.2011 तक प्रस्तुत कर दिये जाने की स्थिति में व्यवहारियों को Deemed Assessment Scheme for Assessment of the Year 2009-10 के अन्तर्गत मानते हुए, सभी तरह की शास्तियां एवं देय ब्याज से मुक्ति प्रदान की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के समस्त रिटर्न्स दिनांक 31.01.2011 तक प्रस्तुत कर दिये गये हैं। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति एवं धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के घोषणा-पत्र तियत समयावधि तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी अधिसूचना दिनांक 16.05.2011 से जारी की गयी Deemed Assessment Scheme for Assessment of the Year 2009-10 के लिये पात्र नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति एवं धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों एवं अधिसूचना दिनांक 16.5.2011 को मद्देनजर रखते हुए ही अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण के कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 25.01.2012 में बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति तथा देय कर विलम्ब से जमा कराने के कारण ब्याज का आरोपण किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा 31.03.2011 तक समस्त विवरणियां प्रस्तुत कर दी थीं तथा देय कर जमा करा दिया गया था। यह तथ्य कर निर्धारण आदेश से भली-भांति पुष्ट है।

मोटी ४

7. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.03.2011 के द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये दिनांक 31.03.2011 तक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में शास्ति एवं ब्याज की राशि को माफ किया गया है। अधिसूचना का सम्बन्धित भाग निम्नानुसार है :—

### NOTIFICATION

No.F.12(25)FD/Tax/11-169

Jaipur, Dated: 30.3.2011

In exercise of the powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-2010, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 31.03.2011.

8. इसी प्रकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.16टैक्स/सीसीटी/11-241 दिनांक 16.5.2011 का बिन्दु संख्या 4 व 5 निम्न प्रकार है :—

Hon'ble Chief Minister (Finance Minister) at para 258 of the Budget Speech 2011-12 has announced that :-

4. **Levy of Penalty and Interest.**- The State Government vide notfn No. F.12(25)FD/Tax/11-01 dated 1-4-2011, as amended from time to time [S.No.V613], have waived penalty and interest levied or likely to be levied on filing of late return and/or late payment of tax for the dealers who have submitted their all returns including annual return or audit report as the case may be, up to 16.5.2011. Thereafter, no penalty or interest shall be levied on late filing of return or late payment of tax against such dealer(s) on the condition that due tax has been deposited up to 16.5.2011 and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted up to 16.5.2011.

5. **Procedure of Deemed Assessment.**- In all such cases, the AA. shall verify the return in the manner prescribed in clause (3) above and shall make a note on the order sheet, after due verification that the net tax payable by the dealer, as per the return, has been deposited into the exchequer and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted by the dealer up to 16.5.2011, therefore, the dealer is being assessed with nil demand under the Deemed Assessment Scheme. Copy of such order sheet shall not be made available to the dealer unless directed by the Dy. Commissioner (Admn.)

लगातार.....4

9. हस्तगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन/परीक्षण पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.16टैक्स/सीसीटी/11-241 दिनांक 16.5.2011 के निर्देशों की पालना नहीं करते हुए शास्ति व ब्याज का आरोपण किया गया है। शास्ति व ब्याज विधिक रूप से आरोपणीय ही नहीं था। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(25) एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.03.2011 के द्वारा शास्ति एवं ब्याज माफ किये जा चुके थे।
10. इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2011 का समुचित रूप से अवलोकन किये बिना धोषणा—पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने को आधार बनाते हुए, कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।
11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 14.01.2013 एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.01.2012 (धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति एवं धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज की सीमा तक) अपास्त किये जाते हैं।
12. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी  
सदस्य  
12.02.201